



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124764

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या - 3462 वर्ष 2026

जय प्रकाश त्रिपाठी

.....आवेदक (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : धर्मेन्द्र कुमार शुक्ला, राजेश कुमार शुक्ला

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य की ओर से विद्वान एजीए को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. वर्तमान प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 05/2017, धारा 419, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता, थाना नौतनवा, जनपद महाराजगंज में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक निर्दोष है और गुप्त उद्देश्य के कारण वर्तमान प्रकरण में गलत तरीके से फंसाया गया है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवाद धन के लेन-देन से संबंधित है, जिसमें आवेदक शामिल नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ने पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से वर्ष 1993 में सरस्वती देवी से प्लॉट संख्या 1176/2 खरीदी है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायतकर्ता प्लॉट संख्या 1176/1 पर एक डिग्री कॉलेज चला रहा है और वह आवेदक के प्लॉट के माध्यम से मार्ग

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चाहता है; जब आवेदक ने इसके लिए इनकार कर दिया, तो उसके खिलाफ झूठी प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में किसी भी समय पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका है, जबकि उसके खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विवेचना/मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया।

5. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और अन्य, (2020)

5 एससीसी 1 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर कानून को अंततः यह कहते हुए तय किया है कि अग्रिम जमानत हमेशा सीमित अवधि की नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त प्रकरण में, यह मुकदमे के समापन तक जारी रह सकता है। इसमें आगे यह व्यवस्था दी गई है कि अभियुक्त के आचरण और व्यवहार के आधार पर दी गई अग्रिम जमानत मुकदमे तक आरोप पत्र दाखिल करने के बाद जारी रह सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आगे यह व्यवस्था दी गई है कि अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा जांच के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने की संभावना, या गवाहों को डराने सहित सबूतों के साथ छेड़छाड़, न्याय से भागने की संभावना, जैसे कि देश छोड़ने पर विचार करना होगा। आदि। यह भी माना गया है कि न्यायालयों को आम तौर पर अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक को जिम्मेदार ठहराया गया भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारों से निर्देशित किया जाना चाहिए, जबकि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि अग्रिम जमानत दी जाए या इसे अस्वीकार किया जाए। अनुदान देना है या नहीं देना यह विवेक का प्रकरण है।

6. अग्रिम जमानत, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरे विचार में, यह मुकदमे तक आवेदक को अग्रिम जमानत के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

7. आवेदन को तदनुसार स्वीकृत किया जाता है।

8. आवेदक जय प्रकाश त्रिपाठी को निर्देशित किया जाता है कि वह आज से 15 दिनों की अवधि के भीतर इस आदेश की एक प्रति सहित विवेचना अधिकारी/संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हो तथा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो-दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करे। तत्पश्चात उसे विचारण की समाप्ति तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक प्रकरण में निर्धारित तारीख को संबंधित विवेचना अधिकारी/न्यायालय के समक्ष स्वयं को उपस्थित करेगा और विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस कार्यालय में ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे उसके द्वारा संबंधित एस.एस.पी./एस.पी. के पास जमा करना होगा।

9. किसी भी शर्त के चूक के प्रकरण में, यह आवेदक को दी गई सुरक्षा को रद्द करने का आधार हो सकता है।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

2 जून 2026

एस.के.